प्रस्ताव

25 धन जमानत को सार्वजनिक सुरक्षा और देश या क्षेत्र से बाहर भागने की कोशिश पर आधारित प्रणाली के साथ प्रतिस्थापित करने संबंधी कानून पर जनमत-संग्रह।

आधिकारिक शीर्षक और सारांश महान्यायवादी द्वारा तैयार किया गया

इस विधेयक के टेक्स्ट को राज्य सचिव की वेबसाइट *voterguide.sos.ca.gov* पर देखा जा सकता है।

"हाँ" का मत मंजूरी देता है, और "नहीं" का मत ख़ारिज करता है 2018 के ऐसे कानून को जिसने:

- (मुकदमे से पहले जेल से रिहाई प्राप्त करने के लिए) धन जमानत प्रणाली को सार्वजनिक सुरक्षा और देश या क्षेत्र से बाहर भागने की कोशिश के निर्धारण पर आधारित प्रणाली से प्रतिस्थापित किया।
- अधिकांश तुच्छ जुर्म/दुराचार अपराधों में मुकदमे से पहले व्यक्ति की जेल में हिरासत को सीमित करता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर पड़ने वाले शुद्ध राजकोषीय प्रभाव का विधायी विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- मुकदमे से पहले लोगों को जेल से रिहा करने के लिए नई प्रक्रिया के लिए राज्य और स्थानीय लागतों में वार्षिक रूप से संभवत: मध्यम करोड़ों डॉलरों की वृद्धि। यह अस्पष्ट है कि क्या कुछेक बढ़ी हुई राजकीय लागतें इस प्रकार के कार्यभार पर वर्तमान में खर्च किए जाने वाले स्थानीय धन द्वारा प्रति संतुलित की जाएंगी।
- काउंटी जेल लागतों में संभवतः प्रति वर्ष उच्च करोड़ों डॉलरों की कमी।
- सामान्यतः मुकदमे से पहले जेल से रिहाई के लिए भुगतान करने की बजाय लोगों द्वारा सामानों पर धन खर्च करने से संबंधित राज्य और स्थानीय कर राजस्वों पर अज्ञात सकल प्रभाव।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

मुकदमे से पहले जेल से रिहाई दो तरीकों से हो सकती है

गिरफ्तारी के बाद जेल में रखना। अपराध का अभियोग की कार्रवाई लगे हुए लोगों को परीक्षण न्यायालय में वास्तविक मामले की सुनवाई से पहले परीक्षण न्यायालय की कार्रवाइयों में शामिल होना होगा। पहली अदालत की कार्यवाही—जिसे अभियोग की कार्रवाई के रूप में भी जाना जाता है—इसमें न्यायालय को उन लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी देना और ज़रूरत होने पर एक वकील की नियुक्ति करना शामिल है। गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों को अभियोग की कार्रवाई से पहले काउंटी जेल ले जाया जाता है। जेल चलाने वाले काउंटी शेरिफ व्यक्ति को तुरंत रिहा करने या व्यक्ति को जेल में रखने का विकल्प चुन सकते हैं।

मुकदमे से पहले जेल से रिहाई। राज्य के संविधान के तहत, गिरफ्तार किए गए और काउंटी जेल में रखे गए लोगों को—कुछ गुंडागर्दी वाले अपराधों को छोड़कर—मुकदमे से पहले छोड़े जाने का अधिकार है। संविधान निर्दिष्ट करता है कि इन लोगों को ऐसी शर्तों के तहत रिहा किया जाए जो अत्यधिक नहीं हैं। मुकदमे से पहले किसी व्यक्ति को रिहा करने से संबंधित निर्णय लेते समय, परीक्षण न्यायालय को उस व्यक्ति पर (1) लगाए गये अपराध के आरोपों की गंभीरता पर, (2) व्यक्ति के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और (3) अदालत में उपस्थित होने की व्यक्ति की संभावना पर विचार करना चाहिए। न्यायालय इन निर्णयों को करने में मदद करने के लिए जोखिम मूल्यांकन उपकरण (नीचे अधिक विस्तार से चर्चा की गई) सहित जानकारी के विभिन्न हिस्सों का उपयोग कर सकते हैं।

राज्य कानून के तहत, आम तौर पर लोगों को दो तरीकों में से एक में मुकदमे से पहले जेल से रिहा किया जाता है:

- ***खुद का मुचलका।*** परीक्षण न्यायालय लोगों को अपने "खुद के मुचलके" (Own Recognizance, OR) पर रिहा कर सकते हैं, जो आम तौर पर भविष्य की आवश्यक अदालती कार्यवाही में एक व्यक्ति के वादे को संदर्भित करता है। जेल चलाने वाले काउंटी शेरिफ भी कुछ शर्तों के तहत अथवा पर लोगों को रिहा कर सकते हैं।
- ***जमानत।*** लोगों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। जमानत आमतौर पर एक वित्तीय गारंटी को संदर्भित करता है कि व्यक्ति अदालत में आवश्यकतानुसार पेश होगा।

मुकदमे-पूर्व जोखिम के मूल्यांकन के लिए उपकरण। मुकदमे से पहले लोगों को रिहा करने के बारे में निर्णय लेने में मदद करने के लिए, अधिकांश अदालतें और काउंटियां जोखिम (या संभावना) का आंकलन करने के लिए उपकरणों का उपयोग करती हैं, कि रिहा किया गया व्यक्ति एक नया अपराध करेगा या अदालत में पेश होने में विफल रहेगा। ये उपकरण अनुसंधान के आधार पर विकसित किए गए थे जो कुछ लक्षणों वाले लोगों (जैसे कि युवा होने के नाते) में एक नया अपराध करने या अदालत में पेश होने में विफल होने की अधिक संभावना है। उपकरण लोगों के लक्षणों के आधार पर अंक प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक उपकरण उन लोगों को अधिक अंक प्रदान करता है जो 22 वर्ष से कम आयु के हैं क्योंकि उनके ज़्यादा उम्र वाले लोगों की तुलना में अपराध करने की संभावना अधिक है। इसी तरह, जो लोग अतीत में कई बार अदालत

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी है

में पेश होने में असफल रहे, उनके भविष्य में पेश होने की संभावना कम है और उन्हें अधिक अंक प्राप्त होंगे। किसी व्यक्ति का जोखिम स्तर कुल प्राप्त अंकों से निर्धारित होता है। इस जोखिम स्तर का उपयोग यह तय करने में मदद करने के लिए किया जाता है कि क्या और किन परिस्थितियों में व्यक्ति को छोड़ा जाना चाहिए।

जमानत पर रिहाई

प्रत्येक परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित जमानत राशि। राज्य कानून आवश्यक बनाता है कि प्रत्येक काउंटी में परीक्षण न्यायालय एक जमानत अनुसूची को अंगीकृत करे। यह अनुसूची प्रत्येक अपराध पर रिहाई के लिए आवश्यक जमानत की राशि को सूचीबद्ध करती है। जमानत अनुसूची आमतौर पर काउंटी के द्वारा घट-बढ़ सकती है, लेकिन अधिक गंभीर अपराधों के लिए अधिक जमानत की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, वर्तमान Los Angeles काउंटी जमानत अनुसूची में जालसाजी के लिए $20,000 और किसी घर में आगजनी के लिए $250,000 की आवश्यकता होती है।

जमानत दो तरीकों से दी जाती है। ये तरीके हैं:

- ***न्यायालय को व्यक्ति द्वारा दिया गया।*** एक व्यक्ति प्रशिक्षण न्यायालय को नकद, संपत्ति या अन्य वस्तुएं प्रदान कर सकता है जो रिहाई के लिए आवश्यक जमानत की राशि के बराबर है। यह आम तौर पर वापस कर दिया जाता है यदि व्यक्ति आवश्यकतानुसार अदालत में पेश होता है।
- ***जमानत एजेंट द्वारा प्रदान किया गया।*** एक व्यक्ति जमानत एजेंट को एक बीमा कंपनी द्वारा समर्थित जमानत बांड खरीदने के लिए एक नहीं लौटाए जाने वाले शुल्क का भुगतान कर सकता है। यह शुल्क आम तौर पर व्यक्ति की जमानत राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। बांड प्रदान करके, जमानत एजेंट पूरी जमानत राशि का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता है यदि व्यक्ति अदालत में आवश्यकतानुसार पेश नहीं होता है। यदि ऐसा होता है, तो जमानत एजेंट व्यक्ति से पुनर्भुगतान की मांग कर सकता है।

पेश होने में विफलता शायद ही कभी पूर्ण जमानत भुगतान में परिणत होती है। यदि कोई व्यक्ति आवश्यकतानुसार न्यायालय में पेश नहीं होता है, तो न्यायालय यह तय कर सकता है कि जमानत देय है। राज्य कानून परिभाषित करता है कि कब पूर्ण जमानत राशि का भुगतान किया जाना होगा। उदाहरण के लिए, जमानत का भुगतान नहीं किया जाता है, यदि व्यक्ति को न्यायालय के फैसले के 180 दिनों के भीतर कानून प्रवर्तन या जमानत वसूली कर्मचारियों (कभी-कभी "बाउंटी हंटर" कहा जाता है) द्वारा हिरासत में वापस ले आया जाता है। अन्य मामलों में भी जमानत का भुगतान नहीं किया जाता है, जैसे कि यदि न्यायालय बीमा कंपनी को ठीक से सूचित करने में विफल रहता है कि जमानत का भुगतान किया जाना ज़रूरी है। नतीजतन, जमानत का वास्तव में केवल कुछ ही मामलों में भुगतान किया जाता है। काउंटियों और शहरों को यह जमानत भुगतान प्राप्त होता है।

जमानत बांड राज्य द्वारा विनियमित है। इसमें लगभग 2,500 जमानत एजेंटों को लाइसेंस देना और लगभग 20 बीमा कंपनियों द्वारा ऐसे जमानत बांड देने के लिए लगाए गए शुल्क की निगरानी करना शामिल है, जो इन बॉन्ड्स का समर्थन करती हैं। राज्य जमानत एजेंटों और बीमा कंपनियों के खिलाफ प्रशासनिक रूप से शिकायतों की जांच भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्थानीय सरकारों के साथ अदालतों में जमानत एजेंटों और बीमा कंपनियों द्वारा आपराधिक उल्लंघनों के खिलाफ काम करता है। राज्य विनियमन लागतों का समर्थन में सहायता के लिए शुल्क लेता है।

2018 में, जमानत उद्योग ने जमानत बांडों में लगभग $6 बिलियन जारी किए और जमानत बांड शुल्क में लगभग $560 मिलियन एकत्र किए। बीमा कंपनियों को इन शुल्कों पर 2.4 प्रतिशत राज्य बीमा कर देना आवश्यक है—जो 2018 में लगभग $13 मिलियन था।

मुकदमे से पहले जेल से रिहाई अलग-अलग समय पर हो सकती है

अभियोग की कार्रवाई से पहले की रिहाई प्रक्रिया। कुछ अपराधों के लिए जमानत अनुसूची में सूचीबद्ध जमानत प्रदान करने के बाद लोगों को आम तौर अभियोग की कार्रवाई से पहले रिहा किया जा सकता है। कुछ काउंटियों में, परीक्षण न्यायालय अन्य संस्थाओं (जैसे काउंटी परिवीक्षा विभाग) को कुछ लोगों को अभियोग की कार्रवाई से पहले खुद के मुचलके पर रिहा करने की अनुमति दे सकती है। इन लोगों को कुछ शर्तों (जैसे काउंटी परिवीक्षा कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से मिलना) का पालन करना आवश्यक हो सकता है। जो जमानत नहीं देते हैं या खुद के मुचलके पर रिहा नहीं होते हैं, वे अभियोग की कार्रवाई होने तक बंदी रहते हैं।

अभियोग की कार्रवाई के बाद की रिहाई प्रक्रिया। अभियोग की कार्रवाई पर न्यायालय यह तय करता है कि क्या (1) लोगों को जेल में रखा जाए, (2) रिहाई के लिए आवश्यक जमानत की राशि में परिवर्तन किया जाए या (3) व्यक्ति को खुद के मुचलके पर रिहा किया जाए। वे लोग जो खुद के मुचलके पर रिहा नहीं होते हैं और आवश्यक जमानत प्रदान करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें आमतौर पर काउंटी जेल में रखा जाता है। न्यायालय रिहा होने वालों पर कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक बना सकता है। कुछ मामलों में, लोगों से मुकदमा-पूर्व रिहाई से संबंधित शुल्क लिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की लागत के लिए शुल्क लिया जा सकता है, जो अदालत द्वारा आदेशित एक शर्त हो सकती है। अदालत इन फैसलों को तब तक के लिए संशोधित कर सकती है जब तक कि मुकदमा या मामला अन्यथा हल न हो जाए।

2018 में नए जमानत और मुकदमा-पूर्व कानून का पारित होना

2018 में, जमानत को खत्म करने और मुकदमे से पहले जेल से रिहा होने की प्रक्रियाओं को बदलने के लिए विधान मंडल ने एक कानून सीनेट बिल (SB) 10—को पारित किया और गवर्नर ने

प्रस्ताव
25
धन जमानत को सार्वजनिक सुरक्षा और देश या क्षेत्र से बाहर भागने की कोशिश पर आधारित प्रणाली के साथ प्रतिस्थापित करने संबंधी कानून पर जनमत-संग्रह।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण जारी है

कानून पर हस्ताक्षर किए। यह कानून 1 अक्टूबर, 2019 से लागू होता। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि SB 10 पर एक जनमत संग्रह ने इसे जनवरी 2019 में इस मतपत्र के लिए योग्य बना दिया। राज्य के संविधान के तहत, जब एक नए राज्य कानून पर जनमत संग्रह मतपत्र के लिए योग्य बन जाता है, तो कानून तब तक लागू नहीं होता है, जब तक मतदाता यह निर्धारित नहीं कर लेते हैं कि इसे लागू करना है या नहीं।

प्रस्ताव

निर्धारित करता है कि क्या नया जमानत और मुकदमा-पूर्व कानून प्रभावी होना चाहिए। प्रस्ताव 25 SB 10 पर एक जनमत संग्रह है और यह निर्धारित करेगा कि क्या बिल प्रभावी होगा। एक "हां" में मतदान का मतलब है कि SB 10 प्रभावी हो जाएगा और एक "नहीं" में मतदान SB 10 को खारिज कर देगा। विशेष रूप से, इस प्रस्ताव की स्वीकृति (1) जमानत पर रिहाई को समाप्त कर देगी, (2), अभियोजन से पहले रिहाई के लिए एक नई प्रक्रिया का निर्माण करेगी, और (3) अभियोजन पर रिहाई के लिए मौजूदा प्रक्रिया को बदल देगी।

जमानत पर रिहाई को खत्म कर देता है

प्रस्ताव 25 मुकदमे से पहले जमानत पर काउंटी जेल से रिहाई को समाप्त कर देता है।

अभियोजन से पहले रिहाई के लिए नई प्रक्रिया बनाता है

अधिकतर छोटे अपराधों में स्वचालित रिहाई आवश्यक बनाता है। यह प्रस्ताव आवश्यक करता है कि छोटे अपराधों जो गुंडागर्दी से कम गंभीर अपराध हैं, के लिए काउंटी जेल में रखे गये लोग 12 घंटे के भीतर स्वचालित रूप से रिहा हो जाएँ। छोटे अपराधों के लिए जेल में रखे गए कुछ लोग, जैसे कि घरेलू हिंसा के लिए जेल में रखे गए या जो पिछले साल में दो बार से अधिक बार न्यायालय में पेश होने में विफल रहे हैं, स्वचालित रूप से रिहा नहीं किए जाएंगे।

गुंडागर्दी और कुछ छोटे अपराधों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यह प्रस्ताव आवश्यक बनाता है कि जेल में रखे गये (1) गुंडागर्दी करने वालों और (2) उन छोटे अपराधियों को जो स्वत: रिहाई के लिए अयोग्य हैं, उनका एक नया अपराध करने या रिहा होने पर अदालत में पेश होने में विफल रहने के जोखिम के लिए मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन कर्मचारी कुछ जानकारी एकत्र करेंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जोखिम के स्तर को दर्शाया जाएगा जिसे एक मुकदमा-पूर्व जोखिम मूल्यांकन उपकरण द्वारा निर्धारित किया गया है। आमतौर पर कर्मचारियों के लिए कम जोखिम वाले लोगों को छोड़ने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक परीक्षण न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर, कुछ मध्यम-जोखिम वाले लोग भी मूल्यांकन कर्मचारियों द्वारा या एक न्यायाधीश द्वारा रिहा किए जाएंगे। रिहा होने वालों को कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक हो सकता है। इन शर्तों में पर्यवेक्षण शामिल हो सकता है, जैसे काउंटी जांच कर्मचारियों या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ नियमित चेक-इन। हालांकि, कम जोखिम वाले लोगों की शर्तों में पर्यवेक्षण शामिल नहीं हो सकता है। न्यायालय उचित कारण से इन शर्तों को बदल सकता है। वर्तमान कानून के विपरीत, रिहाई की शर्त के रूप में कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है। उच्च जोखिम वाले लोग, मध्यम-जोखिम वाले लोग जो रिहा नहीं होते हैं, और कुछ अन्य लोग (जैसे कि कुछ गंभीर गुंडागर्दी के आरोप वाले, जिनमें हत्या या घर की आगजनी भी शामिल है), अभियोग की कार्रवाई तक काउंटी जेल में रहेंगे। किसी व्यक्ति को जेल में रखने के 36 घंटों के अंदर मूल्यांकन और किसी रिहाई को पूरा किया जाना ज़रूरी होगा।

मुकदमा-पूर्व मूल्यांकन के लिए परीक्षण न्यायालय उत्तरदायी हैं। प्रस्ताव 25 मुकदमा-पूर्व मूल्यांकन के लिए राज्य परीक्षण न्यायालय को उत्तरदायी बनाता है। इसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, जैसे: (1) मुकदमा-पूर्व जोखिम मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करके जोखिम के स्तर का निर्धारण करना, (2) किसी व्यक्ति के जोखिम से संबंधित अतिरिक्त जानकारी एकत्र करना, (3) कुछ लोगों को उनके जोखिम के स्तर के आधार पर रिहा करना और (4) न्यायालय को मुकदमा-पूर्व रिहाई के लिए शर्तों का सुझाव देना। परीक्षण न्यायालय इन गतिविधियों को करने के लिए मूल्यांकन कर्मी के रूप में न्यायालय के कर्मचारियों का उपयोग या कुछ स्थानीय सार्वजनिक एजेंसियों (जैसे काउंटी परिवीक्षा विभाग) के साथ अनुबंध कर सकता है। यदि न तो न्यायालय और न ही कोई मौजूदा स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी ऐसा करने के लिए तैयार होगी या करने में अक्षम होगी, तो न्यायालय इन गतिविधियों को करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक नई स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी के साथ अनुबंध कर सकता है।

अभियोग की कार्रवाई पर रिहाई की प्रक्रिया में बदलाव

अभियोग की कार्रवाई पर, जेल में बंद लोग आमतौर पर खुद के मुचलके पर रिहा कर दिये जाएंगे। जिला अटॉर्नी लोगों को जेल में हिरासत में करने के लिए एक सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं, भले ही वे पहले रिहा किए गए हों। लोगों को केवल कुछ परिस्थितियों में हिरासत में लिया जाएगा — जैसे कि अगर अदालत ने फैसला किया कि ऐसी कोई स्थितियाँ मौजूद नहीं है जो यह सुनिश्चित कर सकें कि वे अपराध नहीं करेंगे या अदालत में पेश होने में विफल रहेंगे। रिहा किए जाने वालों को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ सकता है, लेकिन रिहाई की शर्त के रूप में शुल्क नहीं लिया जा सकता है। अभियोग की कार्रवाई के बाद, जिला अटॉर्नी या लोक अभियोजक कुछ परिस्थितियों में निरोध सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं, जैसे कि अगर मामले में कोई नया सबूत पेश किया गया हो। न्यायालय कुछ परिस्थितियों में खुद के मुचलके संबंधी निर्णय या रिहाई की शर्तों को संशोधित कर सकता है, जैसे कि मुकदमा-पूर्व मूल्यांकन कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई नई जानकारी।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण जारी है

वित्तीय प्रभाव

प्रस्ताव 25 का राज्य और स्थानीय दोनों लागतों पर प्रभाव पड़ेगा। इन प्रभावों का वास्तविक आकार अनिश्चित है और यह निर्भर करेगा कि प्रस्ताव की व्याख्या और कार्यान्वयन कैसे किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट नहीं है कि न्यायालय कितने लोगों को मुकदमा-पूर्व और शर्तों का पालन करने के अधीन रिहा करेगा। जैसे, प्रभाव नीचे के अनुमानों की तुलना में अधिक या कम हो सकते हैं।

राज्य और स्थानीय मुकदमा-पूर्व रिहाई की लागतों में वृद्धि। नई मुकदमा-पूर्व रिहाई प्रक्रिया राज्य परीक्षण अदालतों, साथ ही काउंटी जिला वकीलों और लोक अभियोजकों के लिए कार्य का भार बढ़ाएगी। उदाहरण के लिए नई हिरासत सुनवाईयों से संबंधित काम का बोझ होगा। काम के बोझ में इस वृद्धि का प्रति संतुलन दूसरे कामों के बोझ में कमी से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जमानत की राशि के बारे में सुनवाई से काम का बोझ समाप्त हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य की लागतों में वृद्धि होगी क्योंकि राज्य परीक्षण अदालतें मुकदमा-पूर्व मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। राज्य में पर्यवेक्षण की लागतों में वृद्धि होने की संभावना भी होती है, जैसे कि मुकदमा-पूर्व रिहाई होने के बाद पर्यवेक्षण किए जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण।

कुल मिलाकर, **बढ़ी हुई राज्य और स्थानीय मुकदमा-पूर्व लागतें सालाना सैंकड़ों मिलियन डॉलरों में हो सकती है**। यह राशि राज्य के वर्तमान सामान्य निधि बजट के 1 प्रतिशत से कम है। लागतों में वृद्धि का वास्तविक आकार अनेक कारकों पर निर्भर करेगा। प्रमुख कारकों में मुकदमा-पूर्व रिहा किए गए लोगों की संख्या, उनकी रिहाई की शर्तें (जैसे कि पर्यवेक्षण की कितनी आवश्यकता है) और इन शर्तों की लागतें शामिल है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या राज्य की कुछ बढ़ी हुई लागतों की मुकदमा-पूर्व कार्यभार पर मौजूदा स्थानीय सरकारी खर्चों से भरपाई होगी।

काउंटी जेलों की लागतों में कमी। यह प्रस्ताव काउंटी जेल की आबादी में कमी करेगा। यह काफी हद तक इसलिए है क्योंकि अधिक लोगों को जेल में रखने की बजाय या तो मुकदमा-पूर्व या खुद के मुचलके पर रिहा कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, कुछ लोग जो जमानत देने में असमर्थ थे, उन्हें मुकदमा-पूर्व प्रक्रिया के तहत रिहा किया जाएगा। हालांकि, जेल की आबादी में इस गिरावट का कुछ अन्य कारकों से प्रति-संतुलन हो सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग—जो अन्यथा जमानत पर रिहा हो जाते—मुकदमा समाप्त होने तक हिरासत में रखे जा सकते हैं। कुल मिला कर, हम अनुमान लगाते हैं कि जेल की आबादी में कमी से स्थानीय काउंटी जेलों की लागतों में कमी आएगी, जो संभवत: सालाना दसियों मिलियन डॉलरों के उच्च स्तर पर होगी। वास्तविक कमी जेल में रखे गए लोगों की संख्या के साथ-साथ अदालतों द्वारा जारी फैसले पर निर्भर करेगी। इन संसाधनों को संभवतः काउंटी की अन्य गतिविधियों के लिए पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

राज्य और स्थानीय कर राजस्व पर प्रभाव। इस प्रस्ताव का राज्य और स्थानीय दोनों लागतों पर प्रभाव पड़ेगा। एक ओर, यह राज्य और स्थानीय कर राजस्वों को कम करेगा। उदाहरण के लिए, बीमा कंपनियां अब जमानत बांड शुल्क पर करों का भुगतान नहीं करेंगी। दूसरी ओर, राज्य और स्थानीय कर राजस्वों में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, लोग उस पैसे से सामान खरीद सकते हैं, जो अन्यथा जमानत बांड फीस पर खर्च किए जाते थे। अगर ये सामान बिक्री कर के अधीन होते हैं, तो इससे राज्य और स्थानीय कर राजस्वों दोनों में वृद्धि होगी। राज्य और स्थानीय राजस्वों पर कुल शुद्ध प्रभाव अज्ञात है।

प्रमुख रूप से इस उपाय का समर्थन या विरोध करने के लिए बनाई गई समितियों की सूची के लिए *http://cal-access.sos.ca.gov/campaign/measures/* पर जाएं।

समिति के शीर्षस्थ 10 योगदानकर्ताओं तक पहुंचने के लिए *http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html* पर जाएं।

यदि आप इस राज्य के उपाय के संपूर्ण टेक्स्ट की एक प्रतिलिपि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो कृपया राज्य सचिव को (888) 345-2692 पर कॉल करें या आप *vigfeedback@sos.ca.gov* पर ईमेल भेज सकते हैं और आपको एक प्रतिलिपि नि:शुल्क डाक द्वारा भेज दी जाएगी।